विष्णु देव शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व आदि

23 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सतशिवम, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226, रिट याचिका - संक्षिप्त में याचिका खारिज - बिना कोई कारण इंगित किये - अभिनिधार्रित आवश्यकता नहीं है - सेवा कानून - वरिष्ठता अनुच्छेद 136 व 226 - रिट याचिका पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय को कारण बताने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जा सकता है - एसएलपी स्तर पर अपीलों को बिना किसी कारण के अस्वीकार करते हुए रिट याचिका के निस्तारण के समय बिना किसी तर्क अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों पर तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 136 किसी भी पक्षकार के पक्ष में अपील करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है - इसके तहत शक्तियाँ विशेष एवं असाधारण हैं और इसका उददेश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता न हो।

न्याय प्रशासनः

न्याय वितरण प्रणाली-निर्णय में तर्क का अधिकार/आदेश-अभिनिर्धारित सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है - न्यायालय द्वारा प्रकरण में मस्तिष्क के उपयोग को इंगित करने के लिए कारण आवश्यक हैं - न्याय का नैसगिर्क सिद्धांत - स्पष्ट आदेश-निर्णय/आदेश।

अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का संक्षिप्त तरीके से निपटारा किया। इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वरिष्ठता सूची में उसे कनिष्ठों से नीचे रखा गया था, जो ऐसा नहीं किया जा सकता और इस रिट याचिका को संक्षिप्त में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि इसमें कई महत्वपूर्ण महत्व के मुद्दे शामिल थे, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, अभिनिर्धारित कियाः

1.1. बिना कोई कारण बताए संक्षिप्त तरीके से रिट याचिका को खारिज करना स्पष्टतया अक्षम्य है। कारण आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय पर स्पष्ट विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को कारणों को इंगित करना चाहिए, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, जिससे कि उनके आदेश में मस्तिष्क का उपयोग इंगित होता हो, क्योंकि उनके आदेश

को आगे और भी चुनौती दी जा सकती है। निणर्य में कारण नहीं देने की वजह से उच्च न्यायालय का निर्णय मानने योग्य नहीं है।

ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971) 1 ऑलईआर 1148; अलेक्जेंडर मशीनरी (डूडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974) एलसीआर 120-संदर्भित।

1.2. कारण आत्मचेतना को निष्पक्षता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को लेखबद्ध किए जाने पर इसलिए जोर दिया जाता है कि, यदि निर्णय "गूढ व्यक्ति का रहस्यमयी चेहरा" प्रकट करता है, तो कारणों के नहीं होने से, न्यायालय के लिए आदेश की वैद्यता के निर्णय के समय अपीलीय कार्य करना या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करना लगभग असंभव होगा। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कारण कम से कम न्यायालय के द्वारा प्रकरण में मस्तिष्क के उपयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। इसका एक अन्य तर्क यह भी है कि प्रभावित पक्ष को यह पता चल सकता है कि फैसला उनके विरुदध क्यों हुआ है। नैसर्गिक न्याय की एक मूलभूत आवश्यकता यह भी है कि, आदेश करने के कारण आदेश में निहित हों, दूसरे शब्दों में, एक स्पष्ट आदेश।

2. किसी भी न्यायिक शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल यह तथ्य कि न्यायालय/मंच के पास किसी भी तरह से

इसका प्रयोग करने का विवेकाधिकार निहित है, इसे किसी भी प्रकार से मनमाने ढंग से करने की अनुज्ञा नहीं मानी जा सकती, जैसा कि प्रसिद्ध कहावत द्वारा व्यक्त किया जाता थाः "कुलाधिपति के पैर के अनुसार भिन्न-भिन्न।" मनमानी हमेशा न्यायपालिका के द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों के उपयोग का अभिशाप माना गया है, इसके अलावा, जबकि इस तरह के आदेश आगे उच्च मंचों के समक्ष चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह के अनुष्ठानिक अवलोकन और संक्षिप्त निपटान, जिसका उस समय प्रभाव है, उसे न्यायालयों के समक्ष सही एवं न्यायसंगत निपटारा नहीं कहा जा सकता है। निर्णय में कारणों का देना न्यायालयों के समक्ष मामले के विवेकपूर्ण निपटान के लिए अत्यंत आवश्यक है, और केवल इससे ही यह इंगित होता है कि क्या तरीका और किस गुण्वत्ता के प्रयास किए गए हैं और यह कि संबंधित न्यायालय ने वास्तव में अपना मस्तिष्क का उपयोग किया है।

उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004) 5 एससीसी 568 संदर्भित किया गया।

3. भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत इस न्यायालय की शक्ति पर एक सादृश्य बनाने का प्रयास है और एसएलपी स्तर पर बिना कारण बताए रिट याचिकाओं को अपीलीय स्तर पर अस्वीकार करने की प्रथा का कोई अर्थ नहीं है और अतार्किक है। सर्वप्रथम

उच्च न्यायालय अनुक्रम में अंतिम न्यायालय नहीं हैं और इसके आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए जाने योग्य है, जबकि इसके भिन्न स्पष्ट स्थिति यह है कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति के आदेश को इंकार करने के आदेश की सूरत में आगे किसी भी अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। एक से अधिक अवसरों पर दोहराया गया कि संविधान का अनुच्छेद 136, किसी भी पक्ष को अपील करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि कोई व प्रत्येक त्रुटि को संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों से ठीक किया जा सकता है। इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियां विशेष एवं असाधारण हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता न हो। रिट याचिका के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 619/2008

इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल विविध रिट याचिका सं. 18497/ 1994 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.01.2004 से

अपीलार्थी की ओर से त्रिपुरारी राजा एवं विश्वजीत सिंह।

उत्तरदाताओं की ओर से एस. बी. उपाध्याय, निरंजना सिंह, विमला सिन्हा एवं राज सिंह राणा।

इस न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमती दी गई।

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दीवानी विविध रिट याचिका याचिका संख्या 18497/1994 को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। विवाद वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है।

3. तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिट याचिका का निपटारा संक्षिप्त तरीके से निम्नलिखित अवलोकन कर किया गया थाः

> "यह अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका है। हमने पक्षों के वकीलों को सुना है। वरिष्ठता पुष्टि की तारीख से दी गयी है। हम इसमें कोई अवैधता नहीं पाते हैं। रिट याचिका खारिज की जाती है।"

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका का इस तरह से संक्षिप्त खारिज किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बिन्दु जिनका काफी महत्व है शामिल हैं, विशेष रूप से क्या वरिष्ठता तय करने के लिए जो मापदंड है, उन पर प्रकरण के तथ्यों की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना था।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बताया कि वरिष्ठता सूची में उसे कनिष्ठों से नीचे रखा गया था जो अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया था।

6. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील और उनके अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

7. जैसा कि आदेश के उद्धृत भाग से पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था। इस तरह से बिना कोई कारण बताए संक्षिप्त तरीके से रिट याचिका की बर्खास्तगी को खारिज किया जाना अक्षम्य है।

8. कारण किसी क्रम में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों ना हो अपने दिमाग के उपयोग का संकेत देते हुए अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, खासकर तब जब उनका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को टिकाउ नहीं बना दिया।

9. यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में लॉर्ड डेनिंग एम.आर. ने ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971) 1 ऑलईआर 1148 में कहा है कि "कारण देना एक अच्छे प्रशासन की मूल बातें है।" अलेक्जेंडर मशीनरी (डूडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974) एलसीआर 120

में यह देखा गया थाः कारण बताने में विफलता न्याय से इन्कार करने के बराबर है। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आये निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत कड़ी है। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि यदि निर्णय के ''रहस्य का गुढ चेहरा'' सामने आ जाता है, तो यह अपनी चुप्पी से, न्यायालय के लिये अपना अपीलीय कार्य करना या इसकी वैधता का निर्णय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बन सकता है। तर्क का अधिकार अपरिहार्य है एवं एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का हिस्सा, कम से कम पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिये पयार्प्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि क्यों फैसला उनके खिलाफ गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "एक स्फिंक्स का गूढ चेहरा" आम तौर पर एक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ के साथ असंगत है।

10. इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004) (5) एससीसी 568) में पिछले दो दशकों से पहले के मामलों में व्यक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए ऐसे मामलों के निपटान में कारण दर्ज करने के लिये उच्च न्यायालय की आवश्यकता, कतर्व्य और दायित्व पर जोर दिया

है। न्यायिक मंच द्वारा किसी निर्णय/आदेश और न्यायिक शक्ति की पहचान उसके निर्णय के कारणों का खुलासा करना है और कारणों को बताने पर हमेशा मजबूत प्रशासन न्याय-वितरण प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों में से एक के रूप में जोड़ दिया गया है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि न्यायालय के समक्ष इस मुददे पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की एक अनिवार्य अावश्यकता के रूप में उचित और उचित दिमाग का उपयोग किया गया था। किसी भी न्यायिक शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और केवल यह तथ्य कि न्यायालय/मंच के पास जो विवेक है वह किसी भी तरह से प्रयोग करने के लिए निहित है, इसे सनक या इच्छानुसार ओर मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए कोइ अनुज्ञा नहीं बनता है जैसा कि प्रसिद्ध कहावत में अच्छी तरह से बताया गया है किः ''चांसलर के पैर के अनुसार भिन्न- भिन्न मनमानी करने को हमेशा किसी भी शक्ति के न्यायिक अभ्यास का अभिशाप माना गया है, खासकर तब जब ऐसे आदेशों को उच्च मंचों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इस तरह के कमकांडीय अवलोकन और सारांश निपटान, जिसका प्रभाव कभी-कभी होता है, को अदालतों के समक्ष दावे के विवेकपूर्ण निपटान का उचित और न्यायिक तरीका नहीं कहा जा सकता है। किसी निर्णय के लिए कारण बताना अदालतों के समक्ष किसी मामले के न्यायिक और विवेकपूर्ण निपटान का एक अनिवार्य गुण है।

11. भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में संविधान) के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्ति पर एक सादृश्य बनाने का प्र और यास एसएलपी चरण में अपील को बिना कारण बताए हमेशा खारिज करने की प्रथा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहि और ए रिट याचिका से निपटान में कारणों का नहीं देना अताकिर्क व बेमानी है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय पदानुक्रम में अंतिम अदालत नहीं है और इसके आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, स्पष्ट स्थिति के विपरीत कि अपील के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश से आगे किसी अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक से अधिक अवसरों पर दोहराया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्षकार के पक्ष में अपील का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी त्रुटि ठीक की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां विशेष और असाधारण हैं और मुख्य उददेश्य यह सुनिश्चत करना है कि न्याय की कोइ क्षति न हो। रिट याचिका के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता। फलतः, यह अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

12. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को तर्कसंगत आदेश द्वारा कानून के अनुसार नए

सिरे से निपटान के लिए उनके पास भेजते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुवावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अपील स्वीकार की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मशरूर आलम खान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।